

एससी / एसटी युवाओं द्वारा संचालित कर्नाटक स्टार्टअप योजना एप्लीकेशन फॉर्म टू फंड स्टार्टअप्स

कर्नाटक सरकार। अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के युवाओं द्वारा चलाए जा रहे प्रौद्योगिकी स्टार्टअप को बढ़ावा देने और मजबूत ग्रामीण फोकस के साथ उत्पाद या समाधान विकसित करने के लिए एक महत्वाकांक्षी उन्नाव योजना शुरू की है। कर्नाटक उन्नाव स्कीम एप्लीकेशन फॉर्म 10 अक्टूबर 2018 से www.kalyanakendra.com पर उपलब्ध रहेगा। राज्य सरकार। धनराशि प्रदान करके इन स्टार्टअप्स का समर्थन करेगा जो रु। 50 लाख।

स्टार्टअप के लिए इस तरह की योजना शुरू करने का प्राथमिक उद्देश्य बुढ़ापे के मुद्दों को हल करने के लिए नए विचारों को खोजना है।

कर्नाटक Unnati Scheme 2018 से फंड स्टार्टअप्स को राज्य सरकार। रुपये तक की धनराशि प्रदान करने के लिए उन्नाव योजना शुरू की है। अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों और उन स्टार्टअप्स द्वारा चलाए जा रहे प्रौद्योगिकी स्टार्टअप के लिए 50 लाख जो ग्रामीण फोकस के साथ उत्पाद या समाधान के अधिकारी हैं। लाभार्थियों को 2 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाएगा: -

प्रथम श्रेणी - वे स्टार्टअप जहां SC / ST उद्यमियों के पास प्रबंधन में भूमिका के लिए पर्याप्त हिस्सेदारी है। इस श्रेणी के लिए, केवल 1 मानदंड है, जो कि इस क्षेत्र की परवाह किए बिना विचार काफी अच्छा है।

दूसरी श्रेणी - इसमें वे सभी स्टार्टअप शामिल हैं जो किसी भी समुदाय द्वारा चलाए जा सकते हैं, लेकिन विचार एक संतोषजनक होना चाहिए। यह विचार ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छता, अपशिष्ट पृथक्करण और मशीनीकृत मैला ढोने (मैनुअल मैला ढोने की जगह) जैसे क्षेत्रों में एक वास्तविक दुनिया की समस्या को हल करने के लिए काम करना चाहिए।

इन स्टार्टअप के आविष्कार का स्थायी सामाजिक प्रभाव होना चाहिए और नागरिकों के जीवन में बदलाव लाना चाहिए।

कर्नाटक में उन्नाव स्कीम एप्लीकेशन फॉर्म और चयन प्रक्रिया राज्य सरकार। ने घोषणा की है कि कर्नाटक उन्नाव योजना ऑनलाइन आवेदन फॉर्म आधिकारिक वेबसाइट www.kalyanakendra.com पर उपलब्ध होगा। मंत्री की अध्यक्षता में एक 3 सदस्यीय स्क्रीनिंग समिति प्रस्तावों की स्क्रीनिंग करेगी और रुपये का वित्तपोषण करने के लिए उनकी व्यावहारिकता के आधार पर उनका मूल्यांकन करेगी। चयनित स्टार्टअप को 50 लाख।

अभी के लिए, राज्य सरकार। रुपये का बजट आवंटित किया है। इस योजना के लिए 20 करोड़, लेकिन यदि प्रतिक्रिया अच्छी है, तो धनराशि रुपये तक पहुंच सकती है। 100 करोड़ रु। दूसरी श्रेणी में, शॉर्टलिस्ट किए गए स्टार्टअप ग्रामीण क्षेत्रों में अपने विचारों के पायलट परीक्षण चलाने के लिए

पात्र होंगे। इसके अलावा, चयनित स्टार्टअप समाज कल्याण विभाग के साथ-साथ उद्योग के विशेषज्ञों से मेंटरशिप प्राप्त करने में सक्षम होंगे। पायलटों के सफल समापन पर, उनके उत्पादों को प्रूफ-ऑफ-कॉन्सेप्ट और मार्केट रेडी स्टेज के माध्यम से निर्देशित किया जाएगा।

विभाग प्रशासन और सामाजिक समस्याओं को साझा करेगा जिनके बारे में माना जाता है कि उन्हें तत्काल और स्थायी समाधान की आवश्यकता है। 4 वर्ष से कम के सभी स्टार्टअप, कर्नाटक में एक इकाई के रूप में पंजीकृत हैं, जिनमें से आधे राज्य में कार्यरत हैं।